village commons, institutions and government agencies. The scheme would provide financial assistance up to 25 per cent of the total project cost, after the costs have been appraised, firmed up and cleared for assistance by the concerned banks/financial institutions.

WASTELANDS DEVELOPMENT TASK FORCE

Under this scheme, non-forest wastelands in inaccessible and inhospitable terrains like deserts, mountains, ravines, mine areas, etc. will be developed for sustainable use. It is proposed to enlist the services of a disciplined force of ex-servicemen and the scheme would be operated with the assistance of the Directorate of Territorial Army.

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उठाया गया घाटा

1664. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को इस वर्ष "मार्केट इण्टर्वेशन ऑपरेशन" के कारण घाटा उठाना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह घाटा 1992–93 और 1993–94 में हुए घाटे से कितना अधिक है ;

(ग) घाटे के क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड देश में धारा तेल के मूल्य में वृद्धि को नहीं रोक पाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अरविंद नेताम : (क) से (ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तिलहनों/खाद्य तेलों के बारे में मण्डी हस्तक्षेप संबंधी कार्य 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के उपरान्त 31 मार्च, 1994 से समाप्त हो गए। इसलिए इस वर्ष (1994–95) मण्डी हस्तक्षेप कार्यों के कारण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को घाटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मण्डी हस्तक्षेप कार्यों के समाप्त कर दिए जाने के बाद से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर "धारा" नाम के खाद्य तेल का विपणन कर रहा है।

Dairy Development Project

1665. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minster of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the Dairy Development Projects which are in progress in Madhya Pradesh with the assistance of the National Dairy Development;

(b) the assistance provided to Madhya Pradesh during the last three years for the purpose; and

(c) the details of the Dairy Development Projects likely to be set up in the State along with the cost involved therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) There are no Dairy Development Projects in progress in Madhya Pradesh with the Assistance of the National Dairy Development Board.

(b) The assistance provided to Madhya Pradesh under operation Flood III Programme for other purposes than mentioned in part (a) of the question during the last three years are as under:

Year	Rs. in lakh
1991-92	116.81
1992-93	59.37
1993-94	46.64

(c) No Dairy Development Project is likely to be set up in the State in near future with the assistance of NDDB.